

120

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2017/ 19(120) /XXVII(8)/2012

दिनांक: देहरादून: 03 जनवरी, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करन समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27, वर्ष, 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए भी कर निर्धारण वर्ष 2015-2016 से संबंधित वार्षिक विवरणी दिनांक 31-03-2017 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा की जा सकेगी। दिनांक 31-03-2017 के उपरान्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्राविधानों के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

(अमित सिंह नेगी)

सचिव

सं० || /2017/ 19(120) /XXVII(8)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)

अनुसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 11/2017/19(120)/XXVII(8)/2012 dated 03 January, 2017 for general information.

**Government of Uttarakhand**

**Vitta Anubhag-8**

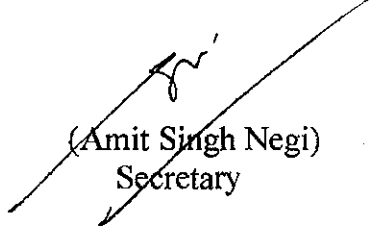
**NO. 11/2017/19(120)/XXVII(8)/2012**

**Dehradun :: Dated:: 03 January, 2017**

**Notification**

Whereas, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding contained in Rule 11 of the Uttarakhand Value Added Tax Rule, 2005, the Governor is pleased to declare that the annual return related to the assessment year 2015-16 may be filed upto 31-03-2017 without any late fee. After 30-03-2017, late fee shall be payable as per provisions of VAT Act and Rules.

  
(Amit Singh Negi)  
Secretary